(c) and (d) Suggestions were received from some members of Parliament during May-August 1997 for re-evaluation of the bids for the Engineering, Procurement and Construction (EPC) contrect for the project. The matter was referred to the JMC. After a careful consideration of the issue involved, the request of Krupp-Uhde for re-evaluation of the EPC bids was rejected by the JMC.

Government approval for investment by RCF and KRIBHCO in the project was accorded on 1.12.97 after due consideration of all the issues relevant to the project, including the selection the selection of the preferred bidder.

Rehabilitation scheme for Namrup Fertilizer Unit

4131. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI KHAGEN DAS:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether any consultancy firm has been appointed for rehabilitation scheme of Namrup Fertilizer Unit of HFC;

(b) if not, the time frame by which the consultancy job would be awarded and whether the same has been included in overall project schedule;

(c) the expected financial involvement in 1998-99;

(d) the major jobs to be taken up under revival scheme in 1998-99;

(e) the conditionalities, if any, for ICICI to fund the scheme;

(f) whether any action is being taken to fulfil the conditionalities; and

(g) if so, the details of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) HFC expects to be able to award the contract for the implementation of the Namrup Revamp Project by August, 1998. This milestone has been included in the overall project schedule.

(c) A budgetary provision of Rs. 70 crore has been earmarked for the rehabilitation scheme during the year 1998-99.

(d) The following activities have been scheduled by the company during the year 1998-99:—

(i) Appointment of a consultant.

(ii) Signing of Memorandum of Understanding with Gas Authority of India Ltd. and Oil India Ltd.

(iii) health study of the plants and definition of project scope, complete basic engineering and detailed engineering, finalisation of specifications and issuance of purchase orders/work orders for the project.

(e) to (g) The indicative conditionalities stiuplated by ICICI in its propsed business plan have been discussed at an interministerial level with a view to addressing the possible concerns of the lenders. The terms and conditions of project financing will be finalised by the lenders after the conclusion of the process of the interaction of HFC with ICICI and other financial institutions.

Implementation of Rehabilitation package for Namrup Unit of HFC

4132. SHRI PARAG CHALIAH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the time frame for implementation of rehabilitation package for Namrup Unit of HFC;

(b) to what extent the production performance of these units will be enhanced after completion of the rehabilitation package; and

(c) whether further delay in completing the reviewing proposals will result in cost escalation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) HFC expects to be able to award the contract for implementation of the Namrup Rehabilitation Project by August 1998. The completion of the Project would take 30 months from the award of the contract.

(b) After implementation of the rehabilitation package, the Namrup Units are likely to produce 5.30 lakh MT of urea per annum as against the average annual production of 1.90 lakh MT during the last three years.

(c) The decision in respect of the rehabilitiation of the Namrup units of HFC has already been taken.

उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में निवेश के संबंध में राष्ट्रीय-स्तर पर गिरावट आना

4133. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय-स्तर पर उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में निवेश में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) और (ख) 1992-93 से देश में निम्नलिखित नई उर्वरक क्षमताओं में वृद्धि हुई है:—

(लाख टन प्रतिवर्ष)

यूरिया	57.24
डी ए पी	1.27
अन्य मिश्रित उर्वरक	5.75
एस एस पी	1.00

(ग) और (घ) उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु अपनाई गई नीति के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:—

(i) घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम तथा भाड़ा सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(ii) उर्वरक उद्योग को फीडस्टाक, ईंधन और रेल संचलन में संयोजन के संबंध में सहायता दी जाती है।

(iii) उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की सामान्यतः आवश्यकता नहीं है।

(iv) उर्वरक उद्योग के लिए पूंजीगत मालों की आपूर्ति के संबंध में आयात शुल्क में छूट तथा निर्यात सम लाभ के रूप में रियायतें दी जाती हैं।

(v) नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायतों की एक स्कीम लागू की गई है ताकि इनके पास्गेट मूल्यों को कम करके इनकी खपत को बढ़ावा दिया जा सके।

(ङ) और (च) यूरिया पर सब्सिडी की वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने एक वैकल्पिक विस्तृत आधार वाली वैज्ञानिक तथा धारदर्शी पद्धति का सुझाव देने तथा इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर लागू नीतियों में और अधिक सामंजस्यता के लिए उपायों की अनुशंसा करने हुते एक उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 3.4.1998 को प्रस्तुत कर दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्धारित किया गया योजना परिव्यय

4134. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कितना योजना परिव्यय निर्धारित किया गया?